



भारतीय वैश्विक
परिषद



रूस-चीन संबंध और बदलती विश्व व्यवस्था

डॉ. हिमानी पंत





भारतीय वैश्विक
परिषद



रुस-चीन संबंध और बदलती विश्व व्यवस्था

डॉ. हिमानी पंत



भारतीय वैश्विक परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय वैश्विक परिषद् को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। परिषद् आज एक आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानो सहित बौद्धिक गतिविधियाँ आयोजित करती है और प्रकाशन करती है। इसमें सुभंडारित पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और 'इंडिया क्वार्टरली' पत्रिका का प्रकाशन करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा दिया जा सके और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। परिषद् की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी है।

रूस-चीन संबंध और बदलती विश्व व्यवस्था

पहली बार प्रकाशित, मई 2023

© भारतीय वैश्विक परिषद्

आईएसबीएन: 978-93-83445-79-0

सर्वाधिकार सुरक्षित। कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों का उत्तरदायित्व विशेष रूप से लेखकों का है और उनकी व्याख्या आवश्यक रूप से भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

भारतीय वैश्विक परिषद

सपू हाउस, बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली 110001, भारत

टेलीफोन: +91-11-2331 7242 | फ़ैक्स: +91-11-2332 2710

www.icwa.in

विषय-सामग्री

सार.....	5
1. प्रस्तावना.....	7
1.1 पृष्ठभूमि: सोवियत संघ और चीन (1949-1991).....	9
2. 1991 के बाद रूस-चीन संबंधों का विकास.....	14
2.1 2000-2013.....	15
2.2 2013-2023.....	18
2.2.1 2014 यूक्रेन संकट- रूस-चीन संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़.....	18
2.2.2 2022 - वर्तमान: रूस-यूक्रेन संघर्ष.....	21
3. रूस-चीन आर्थिक संबंध.....	25
4. रूस-चीन सैन्य-तकनीकी सहयोग.....	28
5. सुलगते मुद्दे: साझेदारी की सीमाएं.....	33
6. चीन के प्रति रूस की विकसित नीति का आकलन.....	37
निष्कर्ष.....	40



सार

वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष और रूस के आगामी आर्थिक अलगाव ने कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को बढ़ा दिया है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। इसके साथ ही अमेरिका-चीन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई है, विशेषकर आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में। इस भू-राजनीतिक प्रवाह के बीच, रूस-चीन संबंध अपने संबंधों में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की अंतर्निहित विशेषताओं के बावजूद और गहरे हो गए हैं। पिछले तीन दशकों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध काफी विकसित हुए हैं। पेपर चीन के प्रति रूस की उभरती नीति पर जोर देने के साथ रूस-चीन साझेदारी के लिए झड़वों की जांच करता है। यह 1990 के दशक के बाद से रूस-चीन संबंधों के विकास का पता लगाता है।

*संकेताक्षर: रूस, चीन, यूक्रेन, चीन-सोवियत संघर्ष, यूक्रेन संकट,
अमेरिका-रूस, अमेरिका-चीन, भारत*



1. प्रस्तावना

फरवरी 2022 से रूस-यूक्रेन संघर्ष और रूस के आर्थिक अलगाव ने कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को बढ़ा दिया है, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। इसी समय, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस)-चीन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई है क्योंकि दोनों वैश्विक मामलों में प्रभाव और शक्ति के लिए, विशेष रूप से आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस भू-राजनीतिक प्रवाह के बीच, रूस-चीन संबंध अपने संबंधों में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की अंतर्निहित विशेषताओं के बावजूद और गहरे हो गए हैं। वर्षों से मास्को और बीजिंग ने कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर साझा स्थिति व्यक्त की है। 1990 के दशक के बाद से साझेदारी विकसित हो रही है और इसमें सुदृढ़ राजनयिक, रक्षा, आर्थिक और सूचना संबंध शामिल हैं। 2014 में यूक्रेन-रूस और पश्चिम-रूस संबंधों में संकट के बाद इस गतिशीलता को और बढ़ावा मिला। तब से, दोनों के बीच सहयोग का दायरा उनके सामयिक मतभेदों के बावजूद व्यापक हो गया है। अपनी ओर से, दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को एक गठबंधन के रूप में पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है; वे फिर भी अपनी "सीमा के बिना दोस्ती" के बारे में मुखर रहे हैं¹। उनके संबंधों की स्थिति को काफी हद तक "एक अर्ध-गठबंधन, या एंटेट" के रूप में व्याख्या की गई है²।

पिछले वर्ष बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक से पहले उनके गठबंधन विश्वदृष्टि का एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें रूस-चीन सहयोग के "नो-लिमिट" दायरे को रेखांकित किया गया था। हालांकि बयान में संबंधों को एक गठबंधन करार देने से परहेज किया गया है, फिर भी दावा किया गया है कि मॉस्को और बीजिंग के बीच "दोस्ती" ने बदलते अंतरराष्ट्रीय वातावरण और अन्य देशों में परिस्थितिजन्य परिवर्तनों में लगातार लचीलापन दिखाया है। संयुक्त बयान में आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के आधार पर विश्व शक्तियों के बीच एक नए प्रकार के संबंध की स्थापना का आह्वान किया गया, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के साथ उनके साझा असंतोष को दर्शाता है³। मार्च 2023 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस यात्रा के दौरान भी इसी तरह के दृष्टिकोण का अनुमान लगाया गया था। चीनी राष्ट्रपति ने रूस के साथ सहयोग का उल्लेख "सच्चे बहुपक्षवाद को बनाए रखने, एक बहु-ध्रुवीय दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन को अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत बनाने में मदद करने के लिए" किया⁴।

यह पत्र चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंधों के कारकों पर प्रकाश डालता है। यह 1990 के दशक के बाद से रूस-चीन संबंधों के विकास का पता लगाता है और तर्क देता है कि



2014 यूक्रेन संकट ने चीन के प्रति रूस की नीति में एक बड़ा बदलाव लाया। इसमें 24 फरवरी, 2022 से यूक्रेन में सैन्य संघर्ष के बाद रूस-चीन संबंधों में हुए घटनाक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है। अंत में, यह पत्र यह भी नोट करता है कि संबंधों में वर्तमान सकारात्मक रुझानों के बावजूद, उनके समन्वय की कुछ सीमाएं हैं जो आने वाले वर्षों में उनके सहयोग के दायरे को प्रतिबंधित करना जारी रखेंगी।

रूस-चीन संबंधों के वर्तमान रुझानों और उनकी साझेदारी में प्रतिस्पर्धा की अंतर्निहित विशेषताओं को समझने के लिए, निम्नलिखित खंड सोवियत संघ-चीन संबंधों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

II पृष्ठभूमि: सोवियत संघ और चीन (1949-1991)

रूस और चीन 4,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करते हैं और एक इतिहास जो तनाव और अनिश्चितताओं के चरणों का गवाह रहा है। सोवियत संघ और चीन के बीच संबंध 1949 से हैं जब चीन बना था और 1991 में सोवियत संघ के विघटन हुआ था। बीच की अवधि को उत्तार-चढ़ाव के चरणों द्वारा चिह्नित किया गया था। संबंधों की स्थापना के बाद पहले कुछ वर्षों के दौरान, दोनों ने एक-दूसरे के प्रति एक अनुकूल स्वभाव साझा किया और फरवरी 1950 में दोस्ती, गठबंधन और पारस्परिक सहायता की (तीस वर्षीय) संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ इस समय

आर्थिक और सैन्य शक्ति में चीन से बहुत आगे था। इसने कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक क्रेडिट प्रदान करके, प्रौद्योगिकी और उपकरणों की आपूर्ति करके और सोवियत संस्थानों में चीनी कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अपने कौशल और ज्ञान को साझा करने के लिए अपने विशेषज्ञों और तकनीशियनों को भेजकर अपने औद्योगीकरण के लिए चीन को बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान की⁵।

हालांकि, यह अवधि अल्पकालिक थी और 1950 के दशक के अंत में एक दरार फूटने लगी। चीनी सोवियत संघ की विकसित वैचारिक और घरेलू और विदेश नीति लाइन से दूर होने लगे। चीन ने सोवियत संघ को सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए एक मॉडल के रूप में देखा, लेकिन साथ ही इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना। ख्रुश्चेव के सुधार और विशेष रूप से कैम्प डेविड शिखर सम्मेलन जो उन्होंने सितंबर 1959⁶ में अमेरिकी राष्ट्रपति इवाइट आइजनहावर के साथ किया था, इस तथ्य के कारण कि चीन को अभी तक अमेरिका द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। इसके अलावा, भारत के साथ सोवियत संघ के बढ़ते संबंधों के बारे में भी आशंकाएं थीं⁷। इस बीच, जुलाई 1960 में, सोवियत संघ ने सोवियत संघ के विरुद्ध कथित चीनी प्रचार के विरोध में चीन से अपने विशेषज्ञों को वापस ले लिया⁸। इन सभी घटनाक्रमों ने, दूसरों के बीच, धीरे-धीरे अगले वर्षों में तीव्र टकराव और प्रतिद्वंद्विता का मार्ग प्रशस्त किया। 1960 के दशक की शुरुआत में सीमा विवाद शुरू हुआ, और 1963 तक "आदेश



उल्लंघन के खुले आरोपों का व्यापार किया जा रहा था",⁹ जिसका समापन मार्च 1969 में उससुरी नदी द्वीप पर दमांस्की द्वीप पर दोनों के बीच एक बड़े सैन्य संघर्ष में हुआ।

1970 के दशक में, सोवियत संघ का पश्चिम और चीन के साथ एक साथ टकराव था, जबकि यह अफगानिस्तान में भी संलग्न था। वियतनाम-कंबोडिया संबंधों में विकास के बाद मास्को और बीजिंग के बीच संबंध भी खराब हो गए। चीन ने 1978 में कंबोडिया में वियतनामी सैन्य हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया और वियतनाम के विरुद्ध अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस बीच, 1970 के दशक की शुरुआत में, चीन-अमेरिकी तालमेल शुरू हो गया था, जिसने "दशक के अंत तक, रणनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया और सोवियत संघ के विरुद्ध एक प्रारंभिक चीनी-अमेरिकी गठबंधन का नेतृत्व किया"¹⁰।

हालांकि, इन वर्षों में, इस समय के दौरान रूसी नीति निर्माताओं के बीच चीन के साथ बातचीत करने के लिए एक बढ़ती हुई भावना थी क्योंकि सोवियत नेतृत्व अत्यधिक रक्षा व्यय को कम करना चाहता था क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा था। इस बीच, चीन में भी 1976 में माओ त्से तुंग की मौत के बाद और बाद में चार लोगों के गिरावट की हार के बाद पुनर्विचार हो रहा था, जिन्हें चरम सांस्कृतिक क्रांतियों के साथ-साथ सोवियत संघ के साथ संबंधों में तेज गिरावट के लिए जिम्मेदार माना गया था। 1978 में, डेन ज़ियाओपिंग ने एक नया सुधार कार्यक्रम पेश

किया जिसने आर्थिक विकास के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का आह्वान किया, जो सोवियत संघ के साथ कामकाजी संबंध विकसित करके संभव हो सकता है। सितंबर और नवंबर 1979 में, चीनी रूसियों के साथ "सामान्यीकरण" वार्ता में पूर्व शर्तों के बिना भाग लेने के लिए सहमत हुए। इन बैठकों में चार चिंताएं सामने आईं। चीनी पक्ष ने चीन की सीमा से लगे क्षेत्र में सोवियत सशस्त्र बलों की एकतरफा कमी, मंगोलिया से सोवियत बलों की वापसी, वियतनाम को सोवियत समर्थन बंद करने और लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान का आह्वान किया था। बाद में, अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी का मुद्दा भी उठाया गया था¹¹।

1980 के दशक में सुलह की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। संबंधों को सुधारने के लिए प्रमुख कदम सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएसयू) के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव के तहत उठाए गए थे, जिन्होंने 1985 में कार्यभार संभाला था। उनका सुधार कार्यक्रम-पेरेस्ट्रोइका (पुनर्गठन) और ग्लासनोस्ट (खुलापन)-केवल तभी सफल हो सकता है जब अनुकूल बाहरी वातावरण में पश्चिमी देशों के साथ-साथ चीन दोनों के साथ संबंधों में सुधार हो ताकि इसे बड़े पैमाने पर सैन्य-औद्योगिक परिसर में कटौती करने की अनुमति मिल सके। 1986 में सीपीएसयू की 27^{वीं} कांग्रेस से पहले अपने भाषण में, चीन के साथ संबंधों में सुधार की दिशा में एक प्रमुख जोर दिया गया था। पिछली नीति के विपरीत, चीन को एक समाजवादी देश के रूप में स्वीकार किया गया



था¹²। बाद में उसी वर्ष, सोवियत महासचिव ने स्पष्ट रूप से व्लादिवोस्तोक में चीन के साथ संबंधों को सुधारने की सोवियत इच्छा व्यक्त की।

एक ऐसे शहर में बोलते हुए जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से एक कदम दूर है, मैं हमारे संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। ये संबंध कई कारणों से बेहद महत्वपूर्ण हैं, इस तथ्य से शुरू करते हैं कि हम पड़ोसी हैं, कि हम दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करते हैं और हम, हमारे बच्चे और पोते "सदैव और सदैव के लिए" एक-दूसरे के पास रहने के लिए नियत हैं। हाल के वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि सोवियत संघ किसी भी समय, किसी भी स्तर पर चीन के साथ अच्छे पड़ोसी का माहौल बनाने के लिए अतिरिक्त उपायों के सवाल पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं कि सीमा का विभाजन- में कहना चाहूंगा, जोड़ना पसंद करूंगा- हम जल्द ही शांति और दोस्ती की रेखा बन जाएंगे। जहां तक संभव हो, सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने में हमारी प्राथमिकताएं समान हैं। क्यों न एक-दूसरे का समर्थन करें, जहां भी इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा, वहां हमारी योजनाओं को लागू करने में सहयोग क्यों नहीं किया जाए? हम नहीं चाहते कि अमूर नदी की सीमा 'पानी की

बाधा' बने। आइए इस शक्तिशाली नदी के बेसिन को चीनी और सोवियत लोगों के प्रयासों को एकजुट करने दें ताकि वहां उपलब्ध समृद्ध संसाधनों का पारस्परिक लाभ और जल प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सके। इस क्षेत्र में एक अंतर-सरकारी समझौते पर संयुक्त रूप से काम किया जा रहा है। सोवियत सरकार कजाकिस्तान के साथ झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ने वाले रेलमार्ग के निर्माण में मदद करने के मुद्दे के संबंध में एक सकारात्मक जवाब तैयार कर रही है। हमने अंतरिक्ष अन्वेषण में पीआरसी के साथ सहयोग का भी सुझाव दिया है, जिसमें चीनी अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण शामिल हो सकता है¹³।

1987 से, सोवियत संघ ने सुदूर पूर्वी क्षेत्र से अपने सैन्य बल में कमी शुरू की। उसी वर्ष, इसने मंगोलिया में सोवियत सैनिकों की तैनाती को चरणबद्ध करना शुरू कर दिया। इस बीच, चीन ने भी इस समय के आसपास रूस के प्रस्तावों का जवाब दिया। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने 1985 में देश के सैन्य सिद्धांत और रणनीतिक रक्षा नीति को संशोधित किया। सोवियत संघ के साथ टकराव की तैयारी के लिए सशस्त्र बलों को पहले के निर्देश को समुद्री क्षेत्र सहित चीन की परिधि के आसपास स्थानीय और सीमित युद्धों के लिए तैयार करने की दिशा से बदल दिया गया था। 1987 में, एक संयुक्त सोवियत-चीनी आयोग ने भी उससूरी



और अमूर नदियों के साथ सीमा मुद्दे को हल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में काम करना शुरू किया¹⁴। अफगानिस्तान से रूस की वापसी और 1980 के दशक के अंत में कंबोडिया से वियतनाम की वापसी ने 1979 में हुई वार्ता में उठाई गई चिंताओं को भी पूरा किया, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी।

सीमा पर तनाव कम होने के साथ-साथ व्यापार संबंधों में भी इस समय सुधार होने लगा। चीन की सोवियत सैन्य उपकरणों और रक्षा के साथ-साथ नागरिक प्रौद्योगिकियों को खरीदने में रुचि थी, विशेषकर 1989 में तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद पश्चिम द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण। दूसरी ओर, सोवियत संघ की अपनी कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर खपत के सामानों को आयात करने में रुचि थी। इस अवधि में एक निर्णायक क्षण मई 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव की चीन यात्रा थी। यह तीस वर्षों में पहला चीन-सोवियत शिखर सम्मेलन था और दोनों पक्षों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया के पूरा होने को चिह्नित किया। गोर्बाचेव की यात्रा के बाद अप्रैल 1990 में चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग ने मास्को की यात्रा की।

इस चरण के अंतिम वर्षों (1989-1991) में, मई 1991 में सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने से चीन को अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुसार अमूर और उससुरी (दमनस्की द्वीप सहित) पर अधिकांश विवादित द्वीप वापस मिल गए। हालांकि, कई स्थानों

को इस समझौते से बाहर रखा गया था, लेकिन उनकी स्थिति अंततः 2008 में हल हो गई थी, जिस पर बाद में इस पेपर में चर्चा की जाएगी। इन दो घटनाओं ने अपनी साझा सीमा पर बल में कमी को कम करने के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। "डेटेंट" के इस चरण को "दोनों विरोधियों द्वारा अपनी प्रतिद्वंद्विता के प्रबंधन के साधन के रूप में देखा गया था, न कि इसे खत्म करने के रूप में"¹⁵।

2. 1991 के बाद रूस-चीन संबंधों का विकास

सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस-चीन संबंध स्थिर होते रहे और स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास आगे भी जारी रहे¹⁶। संक्रमण के इस चरण के दौरान, रूसी नीति निर्माताओं के बीच चीन से निपटने की भूख नहीं थी क्योंकि यह आर्थिक कठिनाइयों, राज्य निर्माण, चेचन युद्ध और कई अन्य गंभीर चिंताओं से जूझ रहा था। इस बीच, चीन के प्रयास विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अपनी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में राज्य नियंत्रण बनाए रखते हुए निर्यात-संचालित अर्थव्यवस्था के निर्माण पर केंद्रित थे। बोरिस येल्टसिन और जियांग जेमिन के बीच व्यक्तिगत संबंध भी सौहार्दपूर्ण थे लेकिन उनकी बातचीत सीमित रही। 1992 में, रूस और चीन ने सैन्य-तकनीकी सहयोग (एमटीसी) समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने दोनों देशों के बीच एमटीसी के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। बाद में, दोनों पक्षों ने सैन्य-तकनीकी सहयोग पर एक मिश्रित अंतर-सरकारी आयोग भी बनाया, जो



सैन्य-तकनीकी संबंधों के विकास के लिए एक औपचारिक मंच है¹⁷।

रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चुनाव के बाद रूस और चीन के बीच जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। जुलाई 2000 में, राष्ट्रपति पुतिन ने "पहले से ही सुदृढ़ रूसी-चीनी संबंधों को सुदृढ़ करने और द्विपक्षीय संबंधों के लिए दीर्घकालिक संभावनाओं को तैयार करने के लिए" चीन का दौरा किया।"

अपनी अलग-अलग प्राथमिकताओं और हितों के बावजूद, दोनों पक्षों के नेताओं ने इस पूरे दशक में संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में रुचि दिखाई। जैसा कि डेन ज़ियाओपिंग ने उल्लेख किया:

कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोवियत संघ में क्या बदलाव हो सकता है, हमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के आधार पर देश के साथ शांति से संबंध विकसित करना चाहिए, और एक बार फिर वैचारिक बहस शुरू नहीं करनी चाहिए¹⁸।

1996 में, रूस और चीन ने एक रणनीतिक सहकारी साझेदारी की घोषणा की, और बाद में वर्ष 2001 में अच्छे पड़ोसी, दोस्ती और सहयोग के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए। "शंघाई फाइव" का पहला शिखर सम्मेलन, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे, सीमा परिसीमन पर ध्यान केंद्रित करते

हूए 1996 में भी हुआ था। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों पर माँस्को और बीजिंग के बीच राजनीतिक सहयोग को प्रदर्शित किया गया।

2.1 2000-2013

रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चुनाव के बाद रूस और चीन के बीच जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। जुलाई 2000 में, राष्ट्रपति पुतिन ने "पहले से ही सुदृढ़ रूसी-चीनी संबंधों को सुदृढ़ करने और द्विपक्षीय संबंधों के लिए दीर्घकालिक संभावनाओं को तैयार करने के लिए" चीन का दौरा किया। बीजिंग घोषणा में "व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और सैन्य-तकनीकी क्षेत्र में व्यापक सहयोग के विकास को रूसी-चीनी संबंधों में प्रगति, समान और भरोसेमंद साझेदारी और रणनीतिक बातचीत में प्रगति के प्रमुख पहलुओं के बीच" पर प्रकाश डाला गया। संयुक्त बयान में एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अमेरिका की वापसी की भी आलोचना की गई थी¹⁹। इस यात्रा को पश्चिम में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रूसी-चीनी धुरी की शुरुआत के रूप में देखा गया था²⁰।

2000 के दशक की शुरुआत में, मास्को और बीजिंग ने "शंघाई फाइव" को एक ठोस क्षेत्रीय एकीकरण पहल में बदलने के लिए एक परियोजना शुरू की, जिसे बाद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रूप में जाना जाने लगा। जून 2001 में, रूस के नए राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति, जियांग जेमिन



ने एससीओ के दायरे में चार मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों के साथ भेंट की ताकि प्रमुख वैश्विक मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जा सके और मध्य एशिया में अपने राजनयिक और आर्थिक पदचिह्न का विस्तार किया जा सके²¹। इस विकास के एक महीने के भीतर, चीनी राष्ट्रपति 16 जुलाई, 2001 को "दोस्ती और सहयोग की अच्छे पड़ोसी संधि" पर हस्ताक्षर करने के लिए मास्को पहुंचे²²। संधि में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों और सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए दोहराया गया है, जो दोनों देशों के लोगों के मौलिक हितों के अनुरूप है और एशिया और दुनिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए अनुकूल है। यह संधि "अच्छे पड़ोसी, दोस्ती और सहयोग, और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से और व्यापक तरीके से दोनों देशों के बीच समानता और विश्वास की रणनीतिक सहकारी साझेदारी" विकसित करने पर भी सहमत हुई²³।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश इस अवधि के दौरान शेष सभी क्षेत्रीय विवादों को हल करने में कामयाब रहे, जब रूस ने बीजिंग के अन्य दावों को हटाने के बदले में चीन से 337 किमी विवादित भूमि को अलग कर दिया²⁴। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था क्योंकि विवादित क्षेत्र शीत युद्ध के चरम के दौरान सशस्त्र संघर्षों का दृश्य था, जैसा कि पेपर में पहले चर्चा की गई थी²⁵। यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में अमेरिकी "आधिपत्य" का मुकाबला करने की मास्को और बीजिंग की आम इच्छा को दर्शाता

है। समय के साथ, दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान और इराक में युद्धों के विरोध और मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के बारे में अपनी चिंताओं जैसे कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने रुख को संरेखित किया। 2011 में, रूस-चीन संबंधों की प्रकृति को एक व्यापक रणनीतिक और सहकारी साझेदारी में अपग्रेड किया गया था।

इस अवधि के दौरान आर्थिक संबंध भी फले-फूले। 2008 तक, उनके बीच व्यापार बढ़कर \$ 55.9 बिलियन हो गया था, जिसमें 2002 और 2008 के बीच 37 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर थी²⁶। हालांकि, यह एक ऐसा चरण भी था जहां 1990 के दशक के विपरीत, रूस के भीतर चीन को हथियारों के हस्तांतरण के बारे में आशंकाएं बढ़ रही थीं, विशेषकर 2000 के दशक की शुरुआत में। इस चरण के दौरान, रूसी निर्मित हथियारों को घरेलू बाजार में चीनी निर्माताओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, रूस चीन में सुखोई (एसयू-27एसके) लड़ाकू जेट जैसे रूसी उपकरणों की अनधिकृत नकल के बारे में भी चिंतित था, जिसे बाद में रियायती कीमतों पर तीसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया²⁷। दोहराव पर इस चिंता ने रूस को चीनी सेना को अपने सबसे परिष्कृत और उन्नत हथियार बेचने से हतोत्साहित किया।



1990 के दशक के विपरीत, रूस के भीतर चीन को हथियारों के हस्तांतरण के बारे में आशंकाएं बढ़ रही थीं, विशेषकर 2000 के दशक की शुरुआत में। इस चरण के दौरान, रूसी निर्मित हथियारों को घरेलू बाजार में चीनी निर्माताओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, रूस, रूसी उपकरणों की अनधिकृत नकल के बारे में भी चिंतित था।

2.2 2013-2023

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में एक सौहार्दपूर्ण और व्यावहारिक कामकाजी संबंध बनाने की दिशा में प्रवृत्ति को और गति मिली। पुतिन और शी दोनों घरेलू राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और अरब स्प्रिंग के बाद अमेरिकी लोकतंत्र से एक आम खतरे की धारणाओं को साझा कर रहे थे²⁸। रूस 2013 में शी जिनपिंग की पहली राजकीय यात्रा का गंतव्य था, और शी "मॉस्को में रूसी सैन्य कमांड सेंटर का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता" बन गए²⁹।

2.2.1 2014 यूक्रेन संकट-रूस-चीन संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़

यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन में 2014 के संकट ने दोनों देशों को अभूतपूर्व पैमाने के समीप ला दिया। यह संकट यूरोपीय संघ के पूर्वी साझेदारी³⁰ शिखर सम्मेलन की विफलता के बाद शुरू हुआ जब तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच यूरोपीय संघ के साथ एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए³¹। उक्त समझौते से अचानक प्रस्थान पर व्यापक विरोध और छोड़ने के बढ़ते दबाव के साथ, राष्ट्रपति यानुकोविच 22 फरवरी, 2014 को कीव से भाग गए और रूस में शरण ली। इसके तुरंत बाद, रूस ने क्रीमियन प्रायद्वीप में एक (बहस) जनमत संग्रह आयोजित किया और उस पर कब्जा कर लिया। इस बीच, यूक्रेन के रूसी भाषी पूर्वी किनारे-डोनबास क्षेत्र जिसमें डोनेट्स्क और लुगांस्क शामिल हैं-रूस की ओर झुकाव था और झड़पों में उलझा हुआ था।

यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन में 2014 के संकट ने दोनों देशों को अभूतपूर्व समीप ला दिया।

यूक्रेन में संकट ने तनावपूर्ण पश्चिम-रूस संबंधों के एक नए चरण की शुरुआत की। तेजी से विरोधी पश्चिम का सामना करते हुए, रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए एशिया और विशेष रूप से चीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया। अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच मई 2014 में राष्ट्रपति पुतिन की शंघाई यात्रा को एक



विशाल प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देखा गया था। पुतिन की यात्रा के दौरान हुई सबसे उल्लेखनीय घटना रूस के गजप्रोम और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच 400 अरब डॉलर के 30 वर्ष के गैस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था।

यूक्रेन में संकट ने तनावपूर्ण पश्चिम-रूस संबंधों के एक नए चरण की शुरुआत की। तेजी से विरोधी पश्चिम का सामना करते हुए, रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए एशिया और विशेष रूप से चीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया।

पश्चिमी प्रतिबंधों और उसके द्वारा लगाए गए प्रतिवादों का सामना करते हुए, रूस को चीन जैसे अधिक रणनीतिक भागीदारों की आवश्यकता थी क्योंकि चीन के बढ़ते आर्थिक दबाव और वैश्विक मामलों में प्रभाव था। राष्ट्रपति पुतिन ने बार-बार जोर देकर कहा कि रूस का आर्थिक भविष्य चीन के साथ है, जो अग्रणी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अमेरिका को हराने के रास्ते पर है। इस प्रकार, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने मास्को को चीन की धुरी बनाने के लिए मजबूर किया, जिससे दो प्राकृतिक प्रतियोगियों को करीबी रणनीतिक भागीदारों में बदल दिया गया³²। इस प्रकार, एशिया या चीन के लिए रूस की धुरी ने "एक नई 360 डिग्री दृष्टि को चिह्नित किया, जिसमें मास्को एक नए भू-राजनीतिक

निर्माण के लिए एक सुविधाजनक बिंदु के रूप में कार्य करता है: यूरेशिया बड़ा है³³। दोनों देश अब अधिक व्यापक रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बनाने के लिए आगे बढ़े हैं।

बाद में, 7 अप्रैल, 2015 को मास्को में तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अपनी बातचीत के दौरान, रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस-चीन संबंध "अभूतपूर्व उंचाई पर पहुंच गए हैं और द्विपक्षीय सहयोग की संभावना पूरी तरह से दोनों देशों की वास्तविकता और दीर्घकालिक जरूरतों के अनुरूप है"³⁴। कुछ सप्ताह बाद, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नाजी जर्मनी पर जीत के सत्तर वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए मास्को की विजय परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था³⁵। परेड के दिन ही पहली बार चीनी गार्ड ऑफ ऑनर की उपस्थिति भी बढ़ते रूस-चीन संबंधों का प्रतिनिधित्व करती थी।

इसके अलावा, रूस ने इस बैठक के मौके पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के साथ अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू)³⁶ को सुसंगत करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने "यूरेशियन यूरोपीय संघ और सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट के विकास के समन्वय में सहयोग" पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए³⁷। इसने रूस-चीन संबंधों के विकास के लिए एक नई रूपरेखा की शुरुआत को चिह्नित किया। बीआरआई-ईएईयू समझौते के ढांचे के तहत, "दोनों पक्षों ने पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए अपने पूरक आर्थिक



लाभों को संरेखित करने का निर्णय लिया और द्विपक्षीय स्तर के साथ-साथ एससीओ के भीतर सहयोग करने पर सहमत हुए³⁸।

2.2.2 2022 - वर्तमान: रूस-यूक्रेन संघर्ष

रूस-चीन संबंधों का एक और महत्वपूर्ण चरण फरवरी 2022 में शुरू हुआ। राष्ट्रपति पुतिन ने 4 फरवरी, 2022 को XXIV ओलंपिक शीतकालीन खेलों³⁹ के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया, ऐसे समय में जब अधिकांश अन्य विश्व नेताओं ने कोरोनावायरस महामारी से चीन के संदिग्ध निपटने को देखते हुए समारोह का बहिष्कार किया। इस अवधि में दिसंबर 2021 में नाटो से सुरक्षा गारंटी की मांग के कारण पश्चिम-रूस तनाव बढ़ने की भी विशेषता थी, जिसमें अमेरिका और नाटो से "किसी भी और विस्तार से बचने" की लिखित प्रतिबद्धता शामिल थी⁴⁰। इन मांगों को पश्चिम ने ठुकरा दिया था और इस दौरान अमेरिका ने कई चेतावनियां भी जारी करनी शुरू कर दी थीं कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है⁴¹।

बीजिंग ओलंपिक से इतर रूस-चीन शिखर सम्मेलन में काफी उत्साह देखने को मिला। इसमें अनुमान लगाया गया है कि रूस और चीन अमेरिका के 'एकतरफावाद' के सामने 'अंतरराष्ट्रीय समानता और न्याय' को बनाए रखने के 'मूल हितों' पर एकमत हैं और 'बाहरी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे' के विरुद्ध एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।

बीजिंग ओलंपिक से इतर रूस-चीन शिखर सम्मेलन में काफी उत्साह देखने को मिला। इसमें अनुमान लगाया गया है कि रूस और चीन अमेरिका के 'एकतरफावाद' के सामने 'अंतरराष्ट्रीय समानता और न्याय' को बनाए रखने के 'मूल हितों' पर एकमत हैं और 'बाहरी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे' के विरुद्ध एक-दूसरे का समर्थन करते हैं⁴²। समारोह से इतर दोनों देश रूस से चीन को गैस की अतिरिक्त आपूर्ति पर सहमत हुए, जिसका भुगतान अमेरिकी डॉलर के बजाय यूरो में करने का निर्णय किया गया⁴³।

उसी महीने, यूक्रेन पर पश्चिम-रूस तनाव चरम पर पहुंच गया जब 21 फरवरी को, रूस ने डोनेट्स्क और लुगांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता दी⁴⁴। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 2014 के यूक्रेन संकट के बाद से रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेनी प्रशासन के बीच उक्त क्षेत्र में लगातार झड़पें जारी थीं। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक (डीपीआर और एलपीआर) के नेताओं ने मई 2014 में यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन 21 फरवरी, 2022 तक किसी भी देश द्वारा इस स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई थी। रूस द्वारा इन अलग हुए क्षेत्रों को मान्यता देने और 21 फरवरी को दोस्ती, सहयोग और पारस्परिक सहायता की संधि के अनुसमर्थन और 24 फरवरी, 2022⁴⁵ को "विशेष सैन्य अभियान" की शुरुआत ने पश्चिम और रूस के बीच शत्रुता का एक नया चरण सामने लाया। यह ऑपरेशन आज भी जारी है और इसने



"फॉल्ट लाइनों को बढ़ा दिया है और क्षेत्रों, महाद्वीपों, राजनीतिक प्रणालियों और आर्थिक रणनीतियों में नए विभाजन खोल दिए हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान उभरे थे"⁴⁶।

रूस-चीन संबंधों और यूक्रेन के विकास के लिए उत्तरार्द्ध की प्रतिक्रिया के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में, चीन ने स्पष्ट रूप से रूस का समर्थन नहीं किया था। इसके बजाय, बीजिंग ने रूस के विरुद्ध मतदान से दूर रहकर संयुक्त राष्ट्र में एक सतर्क रुख अपनाया, क्योंकि इसने दुनिया भर में अपनी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने का भी प्रयास किया। यह ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक देश की उचित सुरक्षा चिंताओं को महत्व दिया जाना चाहिए बीजिंग ने अक्सर संकट को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता का आह्वान किया है। हालांकि, हाल के महीनों में देश की स्थिति धीरे-धीरे रूसी दावों और कार्यों की मौन समझ को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुई है जो अमेरिका और नाटो कार्यों की आलोचना करते हैं। जैसा कि युद्ध ने 24 फरवरी, 2023 को अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया, बीजिंग ने स्थिति से निपटने के लिए "12-सूत्री शांति योजना" का प्रस्ताव रखा, जहां उसने बातचीत, सभी देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए सम्मान और आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने की वकालत की⁴⁷। बाद में, मार्च में, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कार्यालय में अपना तृतीय कार्यकाल शुरू किया, तो उन्होंने रूस का दौरा किया। अपने आगमन वक्तव्य में, राष्ट्रपति शी ने कहा:

रूस-चीन संबंधों और यूक्रेन के विकास के लिए उत्तरार्द्ध की प्रतिक्रिया के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में, चीन ने स्पष्ट रूप से रूस का समर्थन नहीं किया था। इसके बजाय, बीजिंग ने रूस के विरुद्ध मतदान से दूर रहकर संयुक्त राष्ट्र में एक सतर्क रुख अपनाया, क्योंकि इसने दुनिया भर में अपनी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने का भी प्रयास किया।

उन्होंने कहा, 'अस्थिरता और बदलाव की दुनिया में, चीन संयुक्त राष्ट्र के मूल में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों की रक्षा के लिए रूस के साथ काम करना जारी रखेगा। चीन सच्चे बहुपक्षवाद को बनाए रखने, एक बहु-ध्रुवीय दुनिया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अधिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन को अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत बनाने में मदद करने के लिए रूस के साथ काम करेगा'⁴⁸।

इस यात्रा के दौरान, रूस और चीन ने एक नए युग के लिए रूसी-चीनी व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को घनिष्ठ करने



पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, साथ ही 2030 तक रूसी-चीनी आर्थिक सहयोग के प्रमुख तत्वों को बढ़ावा देने की योजना पर रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए⁴⁹। इन बढ़े हुए आर्थिक संबंधों का एक प्रमुख आयाम उनके ऊर्जा सहयोग का विस्तार है और दोनों पक्षों ने मंगोलिया में साइबेरिया-2 गैस पाइपलाइन की नई शक्ति पर भी चर्चा की। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सौदे के अधिकांश मापदंडों पर एक समझौता हुआ है और रूस विश्वसनीय, स्थिर आपूर्ति से 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का निर्यात करेगा⁵⁰।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि दोनों देश जी20 में यूक्रेन संकट को उठाने का संयुक्त रूप से विरोध करेंगे। इसके अलावा, बयान में हिंद-प्रशांत रणनीति के विपरीत एक खुली और समावेशी एशिया-प्रशांत रणनीति बनाने की आवश्यकता का आह्वान किया गया है।

रूस और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के इन विभिन्न चरणों का अवलोकन करने से पता चलता है कि कूटनीति ने दोनों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोवियत संघ के विघटन ने "उनके संघर्ष के लिए वैचारिक बढ़त" को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दोनों देश अपने सीमा विवाद को सफलतापूर्वक सुलझाने में सक्षम थे। 2001 में अच्छे पड़ोसी

और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर; 2000 में राष्ट्रपति पुतिन का सत्ता में आना और 2014 के बाद से यूक्रेन पर पश्चिम के साथ रूस के संबंधों में तेज गिरावट, रूस-चीन साझेदारी में महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही है⁵¹।

हालांकि, जमीन पर कई मतभेद मौजूद हैं, जिन पर बाद में पेपर में चर्चा की जाएगी। निम्नलिखित खंडों में रूस-चीन साझेदारी के दायरे को समझने के लिए संबंधों के दो महत्वपूर्ण स्तंभों-आर्थिक और सैन्य-तकनीकी संबंधों पर चर्चा की गई है।

3. रूस-चीन आर्थिक संबंध

आर्थिक संबंध रूस-चीन साझेदारी का मूल हैं। 2015 के बाद से, रूस ने चीन को अपने तेल निर्यात में 60 प्रतिशत की वृद्धि की है, सऊदी अरब को कच्चे तेल के चीन के शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया है। दिसंबर 2019 में, पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन ने चीन को प्राकृतिक गैस पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा, चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां आर्कटिक क्षेत्र में रूस की परियोजनाओं से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के हितधारक और प्रमुख खरीदार हैं⁵²। 2020 में कोविड-19 से प्रभावित गति के बावजूद, संबंध समृद्ध होते रहे हैं और 2021 में कुल व्यापार में \$ 146 बिलियन से अधिक के साथ पर्याप्त वृद्धि देखी गई है⁵³। इसके अलावा, जबकि दोनों देशों ने 2024 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को 200 बिलियन डॉलर तक



बढ़ाने का इरादा किया था, उन्होंने अब लगातार वृद्धि को देखते हुए मार्क को 250 बिलियन डॉलर तक संशोधित किया है। इस प्रकार वर्तमान आंकड़े वर्षों से निरंतर आर्थिक विकास को दर्शाते हैं।

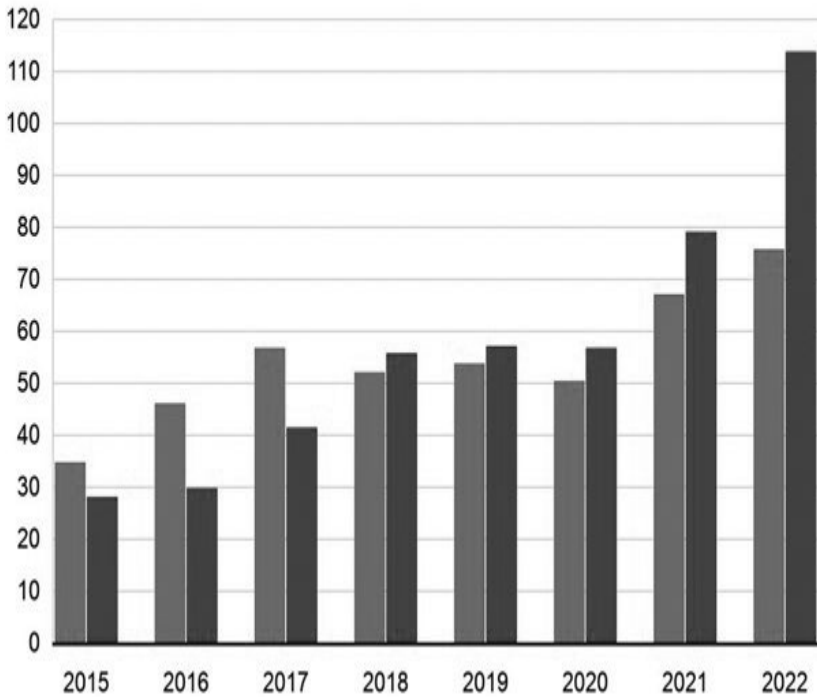
रूस और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के इन विभिन्न चरणों का अवलोकन करने से पता चलता है कि कूटनीति ने दोनों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके अलावा, रूस पर यूक्रेन से संबंधित प्रतिबंधों के बावजूद, चीन के साथ देश का व्यापार 2022 में लगभग 185 बिलियन डॉलर था⁵⁴। चीन को रूस के निर्यात में बड़े पैमाने पर तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, धातु आदि शामिल हैं। यूक्रेन संकट के गहराने के साथ, बीजिंग द्वारा देश पर सभी गेहूं-आयात प्रतिबंधों को हटाने के बाद यह चीन के लिए एक प्रमुख गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरा है। दूसरी ओर, चीन से इसके आयात में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, औद्योगिक सामान और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं जैसे वस्त्र और परिधान, वाहन, जहाज, विमान आदि शामिल हैं।

निम्नलिखित आंकड़े 2015 और 2022 के बीच रूस और चीन के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार को दर्शाते हैं।

रूस का चीन के साथ संवर्धित व्यापार (अमरीकी डॉलर में)

■ चीन से आयात ■ चीन को निर्यात



चित्र: चीन के साथ रूस का बढ़ता व्यापार

स्रोत: बीबीसी; चीनी सीमा शुल्क डेटा

व्यापार की संरचना गहरी होती जा रही है और दोनों देशों ने "2030 तक रूसी-चीनी आर्थिक सहयोग के प्रमुख तत्वों को बढ़ावा देने" के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना में संस्थागत व्यवस्थाओं से चीन-रूस आर्थिक सहयोग के आठ पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें वित्तीय सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा निपटान के अनुपात में



लगातार वृद्धि, ऊर्जा और कृषि जैसे विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों पर सहयोग पर मार्गदर्शन शामिल है⁵⁵।

यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्रा के उपयोग ने चीन को युआन की भूमिका का विस्तार करने का मौका भी दिया है⁵⁶। अमेरिका के साथ चीन की आर्थिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए, व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी में वैकल्पिक वैश्विक प्रणालियों का उपयोग चीन के लिए अपने आर्थिक पदचिह्न का विस्तार करने के लिए उपयोगी है⁵⁷।

कई चिंताओं के बावजूद चीन के साथ रूस के बढ़ते व्यापार के संबंध में ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह एक अनूठी घटना नहीं है। अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और यूरोपीय संघ-चीन प्रणालीगत प्रतिद्वंद्विता के बावजूद, उनके व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में काफी विस्तार हुआ है।

कई चिंताओं के बावजूद चीन के साथ रूस के बढ़ते व्यापार के संबंध में ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह एक अनूठी घटना नहीं है। अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और यूरोपीय संघ-चीन प्रणालीगत प्रतिद्वंद्विता के बावजूद, उनके व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए, उनकी शत्रुतापूर्ण बयानबाजी के बावजूद, 2022 में अमेरिका-चीन व्यापार लगभग 690.6 बिलियन डॉलर था⁵⁸।

4. रूस-चीन सेना-तकनीकी सहयोग

जैसा कि पेपर में पहले उल्लेख किया गया है, रूस ने 1992 में चीन के साथ सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि दोनों पक्षों ने सीमा विवादों को हल किया और जुड़ाव बढ़ाया, रूस ने चीन को अपने हथियारों का निर्यात बढ़ाया। यह प्रवृत्ति 2005-2006 तक जारी रही। 1990 के दशक में हथियारों के हस्तांतरण ने भी उड़ान भरी क्योंकि दोनों देशों के सैन्य उद्योगों ने पारस्परिक निर्भरता के चरण में प्रवेश किया। तियानमेन स्क्वायर⁵⁹ और रूस के चीन को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने के बाद पश्चिमी देशों ने चीन पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया था। यह व्यवस्था रूस के लिए भी लाभप्रद थी क्योंकि वह नए बाजारों की तलाश में था।

हथियारों की बिक्री में गिरावट और दोनों देशों की संबंधित सुरक्षा प्राथमिकताओं में अंतर के कारण उच्च स्थिर हथियारों की आपूर्ति के इस चरण के बाद कूलिंग-ऑफ अवधि हुई। 2006 से 2010 तक, रूस से चीन को प्रमुख हथियार प्रणालियों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ था। इस अवधि के दौरान, मास्को ने रूसी हथियार प्रणालियों की चीनी रिवर्स-इंजीनियरिंग पर चिंता जताई और चीन को अपनी सबसे उन्नत प्रणाली प्रदान करने में संकोच किया। इस अवधि के दौरान एमटीसी में व्यवधान कई कारणों से उपजा था। 2006 तक, चीन रूसी अनुबंध वार्ता नीतियों से नाखुश हो गया था।



अपनी बुनियादी सैन्य आवश्यकताओं को देश में पूरा करने के साथ, चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उन्नत हथियार प्रणालियों और उनकी अंतर्निहित तकनीक खरीदने के लिए रूस की ओर तेजी से देखा। हालांकि, रूस कई कारणों से चीन को अपने सबसे उन्नत सैन्य उपकरणों का निर्यात करने के लिए अनिच्छुक था। माँस्को रूसी सैन्य प्रौद्योगिकी की बीजिंग की बौद्धिक संपदा की चोरी और रूसी हथियार प्रणालियों की बिना लाइसेंस वाली रिवर्स-इंजीनियरिंग के बारे में चिंतित था। रूसी हथियार प्रणालियों की चीन की रिवर्स-इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय उदाहरण पीएलए का जे-11 लड़ाकू है, जो रूस के एसयू 27/एसयू-30 लड़ाकू की एक बिना लाइसेंस वाली प्रतिलिपि है। रूस चिंतित था कि रिवर्स-इंजीनियर रूसी हथियार प्रणालियों के चीनी निर्यात रूस के पारंपरिक हथियार निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे। इसके अलावा, मास्को बीजिंग की बढ़ती सैन्य क्षमताओं से आशंकित था और बीजिंग को उन्नत तकनीक बेचने के लिए तैयार नहीं था जो भविष्य के संघर्ष में रूस के लिए संभावित रूप से खतरा पैदा कर सकता था। यद्यपि चीनी बौद्धिक संपदा की चोरी के बारे में रूसी चिंताओं को कम करने के लिए सैन्य-तकनीकी सहयोग में बौद्धिक संपदा के समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2012 में सुदृढ़ किया गया था, रूस ने चीन को प्रमुख हथियारों की बिक्री से बचना जारी रखा।

चीन को उन्नत हथियार बेचने में रूस की हिचकिचाहट ने 2014 में एक बदलाव देखा। यह 2014 यूक्रेन संकट और अपने पारंपरिक यूरोपीय और पश्चिमी बाजारों से रूस के आर्थिक और राजनीतिक अलगाव के बाद है कि रूस-चीन एमटीसी गहराने लगा। संकट के परिणामस्वरूप रूस का पश्चिम से दूर और बीजिंग की ओर एक बड़ा रणनीतिक पुनर्गठन हुआ। मॉस्को ने बाद में सैन्य-तकनीकी सहयोग सहित चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दी। 2015 में बड़े पैमाने पर हथियारों के हस्तांतरण का नवीनीकरण रूस और चीन के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य-तकनीकी सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत को चिह्नित करता है।

तब से दोनों देशों ने अपने सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। मई 2015 में, रूसी और चीनी नौसेनाओं ने भूमध्य सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। 'ज्वाइंट सी 2015' कोड नाम के इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 17 से 21 मई तक किया गया था और इसमें दोनों देशों के नौ जहाज शामिल हुए थे। यह क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के बारे में नाटो को चेतावनी देने के लिए एक प्रतीकात्मक संकेत था। अभ्यास में "लाइव-फायर अभ्यास, पुनःपूरति और एस्कॉर्ट ऑपरेशन शामिल थे" और रूस के काला सागर बंदरगाह नोवोरोसिस्क में एक संयुक्त कमांड सेंटर की स्थापना की सुविधा प्रदान की, जिसमें चीनी जहाजों ने रूसी जहाजों के साथ



भूमध्य सागर जाने से पहले प्रवेश किया था। इस तरह का सैन्य अभ्यास रूस-चीन संबंधों के इतिहास में पहली बार था⁶⁰। चूंकि 2014 की विजय परेड में शी की उपस्थिति के ठीक एक वर्ष बाद, दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ एकजुटता दिखाने के लिए प्रकाशिकी काफी अधिक थी।

संकट से पहले, रूस चीन के साथ उन्नत रक्षा आपूर्ति साझा करने से सावधान था। इस संबंध में, यूक्रेन संकट की पहली लहर के बाद रक्षा संबंधों के प्रति दृष्टिकोण काफी बदल गया। 2014 के संकट के बाद की अवधि में, दोनों पक्षों ने मई 2015 में शी जिनपिंग और पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित एक बड़े सैन्य हेलीकॉप्टर के संयुक्त डिजाइन और उत्पादन और एक बड़े सैन्य हेलीकॉप्टर के संयुक्त निर्माण पर कई समझौतों में प्रवेश किया, जब शी ने 9 मई की विजय परेड में भाग लिया था। 2014 में, रूस और चीन के केंद्रीय बैंक आरएमबी 150 बिलियन के विदेशी मुद्रा स्वेप पर एक समझौते पर पहुंचे। रूस के क्षेत्र में चीनी निवेश में काफी वृद्धि हुई।

संकट से पहले, रूस चीन के साथ उन्नत रक्षा आपूर्ति साझा करने से सावधान था। इस संबंध में, यूक्रेन संकट की पहली लहर के बाद रक्षा संबंधों के प्रति दृष्टिकोण काफी बदल गया।

रूस के तेल और गैस क्षेत्रों तक पहुंच के अलावा, इसे रूस से उन्नत सैन्य प्रणालियां मिलीं जैसे कि रूस की "लंबी दूरी की एस-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली" और एसयू-35 के लिए लगभग 3 बिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी हथियार सौदा। इन हथियारों के हस्तांतरण ने दोनों देशों के बीच सैन्य-तकनीकी सहयोग में एक नए चरण की शुरुआत की। 2014 के बाद से, मॉस्को-बीजिंग साझेदारी उनकी समझ की दीर्घायु के बारे में लगातार गलतफहमी के बावजूद तेजी से विकसित हुई है। दोनों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक गठबंधन भी पेश किया है, जिसने कई मौकों पर सीरिया पर अमेरिका समर्थित चार प्रस्तावों पर संयुक्त रूप से वीटो किया है। फरवरी 2022 के बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर, चीन ने रूस की सहायता के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया है।

कुल मिलाकर, रूसी-चीनी सैन्य हस्तांतरण ने 2015 में गति देखी। इनमें 2015 में सुखोई-35 लड़ाकू विमान और एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों की बिक्री के लिए ऐतिहासिक अनुबंध शामिल हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टरों, पनडुब्बी प्रौद्योगिकी और विमान इंजनों के हस्तांतरण से जुड़े महत्वपूर्ण लेनदेन की एक श्रृंखला शामिल है। संयुक्त प्रौद्योगिकी परियोजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही हैं क्योंकि मिसाइल रक्षा जैसे नए क्षेत्रों में उनका विस्तार अधिक रणनीतिक महत्व लेता है। संयुक्त अभ्यास, संयुक्त हवाई गश्त और प्रमुख नेताओं की व्यस्तताओं में वृद्धि के साथ, बड़े पैमाने पर हथियारों के हस्तांतरण की



बहाली ने रूस और चीन के बीच बढ़ती सैन्य अभिसरण में योगदान दिया है, जबकि उनकी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया है। ये हस्तांतरण पश्चिमी प्रशांत में चीन के सैन्य विस्तार को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय संतुलन को चीन के पक्ष में अधिक झुकाने में मदद मिल रही है⁶¹। यह 2000 के दशक के मध्य में रूस और चीन के बीच शीतलन अवधि और 2014 के बाद परिणामी वृद्धि को दर्शाता है।

2020-22 में चीन में डिलीवरी की मात्रा 2018-19 की तुलना में बहुत कम स्तर पर थी। यह संभावना है कि आने वाले वर्षों में चीन से ऑर्डर की मात्रा और कम हो जाएगी क्योंकि रूस को अपनी घरेलू खपत के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है⁷⁹। इसके अलावा, चीन रूसी आयात पर कम निर्भर हो रहा है क्योंकि उन्नत प्रमुख हथियारों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है।



चित्र 1 : रूस से चीन को हथियार निर्यात, 1992-2022 (मूल्य \$ मिलियन में)

स्रोत : एसआईपीआरआई आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस⁶⁰

यह ध्यान रखना उचित है कि चित्र 1 भी 2018 के आसपास रूस और चीन के बीच एमटीसी के पठार को इंगित करता है, रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने से बहुत पहले। चीन को रूस के हथियारों के हस्तांतरण का हिस्सा घटने लगा, जो उनके सैन्य-तकनीकी सहयोग में ठहराव की शुरुआत को दर्शाता है। 2020-22 में चीन में डिलीवरी की मात्रा 2018-19 की तुलना में बहुत कम स्तर पर थी। यह संभावना है कि आने वाले वर्षों में चीन से ऑर्डर की मात्रा और कम हो जाएगी क्योंकि रूस को अपनी घरेलू खपत के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है⁶²। इसके अलावा, चीन उन्नत प्रमुख हथियारों के अपने घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बाद रूसी आयात पर कम निर्भर हो रहा है⁶³।



5. महत्वपूर्ण मसलें : साझेदारी की सीमाएं

रूस और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा की अंतर्निहित विशेषताएं आर्कटिक, रूसी सुदूर पूर्व और मध्य एशिया में प्रकट होती हैं। यद्यपि रूस-चीन संबंध गहरे हुए हैं, यह भू-राजनीतिक और भौगोलिक आवश्यकता का परिणाम है। अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के प्रति अपने साझा विरोध के साथ दो बड़े पड़ोसियों के रूप में, सहयोग के लाभ जोखिमों से अधिक हैं। मॉस्को और बीजिंग रणनीतिक रूप से एकध्रुवीयता और अन्य वैश्विक राजनीतिक मुद्दों का विरोध करने के संबंध में एक ही पृष्ठ पर हैं, जैसा कि पेपर में चर्चा की गई है। हालांकि, उनके इतिहास में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, दोनों के बीच विचलन के कई बिंदु हैं जो उनकी साझेदारी के दायरे को सीमित करते हैं। यह स्पष्ट है कि रूस बीआरआई जैसे चीन के नेतृत्व वाले प्रयासों में शामिल होने के बारे में भी सतर्क रहा है, यहां तक कि देश चीन के साथ अपने उद्देश्यों और हितों को सुसंगत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ईएईयू और बीआरआई के एकीकरण के बावजूद, यह ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध ज्यादातर बीआरआई एजेंडे के क्षेत्र के बाहर सीमित हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने परियोजना के लिए घनिष्ठ संबंध और प्रतिबद्धता का दावा करते हुए वर्षों बिताए हैं, रूस काफी हद तक एक अनुपस्थित भागीदार बना हुआ है⁶⁴। इसके अलावा, चूंकि बीआरआई मध्य एशिया में बुनियादी ढांचे के विकास को लक्षित

करता है, "माँस्को द्वारा इसे बहुत संदेह के साथ स्वागत किया गया है, जो इसे अपने आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों के लिए खतरे के रूप में देखता है"। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद से, चीन और मध्य एशिया के देशों के बीच गहरे व्यापार लिंक का विकास इस क्षेत्र में रूसी प्रभाव के क्रमिक क्षरण के समानांतर आगे बढ़ा है⁶⁵। तदनुसार, मास्को ने चीन के बढ़ते वजन और प्रभाव को संतुलित करने के लिए ब्रिक्स, एससीओ, रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय पहल आदि जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के लिए प्रयास किए हैं। इन प्लेटफार्मों को सुदृढ़ करने में रूस के उद्देश्यों को "चीन की श्रेष्ठता को कम करने" में रूस के हित की सेवा के रूप में देखा गया है। मास्को ने चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए ब्रिक्स, एससीओ, रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय पहल आदि जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के लिए प्रयास किए हैं। इन प्लेटफार्मों को सुदृढ़ करने में रूस के उद्देश्यों को "चीन की श्रेष्ठता को कम करने" में रूस के हित की सेवा के रूप में देखा गया है⁶⁶।

रूस और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा की अंतर्निहित
विशेषताएं आर्कटिक, रूसी सुदूर पूर्व और मध्य एशिया
में प्रकट होती हैं।

इसी तरह, संसाधन समृद्ध रूसी सुदूर पूर्व और साइबेरिया में चीन की पहल के संबंध में उसके प्रति भारी अविश्वास है, एक ऐसा क्षेत्र जिसके विकास को रूस ने "21^{वीं} सदी के लिए एक राष्ट्रीय



प्राथमिकता" के रूप में घोषित किया है⁶⁷। जनता की राय प्राकृतिक संसाधनों और कृषि योग्य भूमि पर चीन के "नियंत्रण" के प्रति ज्यादातर नकारात्मक है, जिसे सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय उल्लंघन के रूप में देखा जाता है⁶⁸।

आर्कटिक में रूस-चीन सहयोग में प्रतिस्पर्धा की अंतर्निहित विशेषताएं भी हैं। रूस एक आर्कटिक देश है, जबकि चीन ने खुद को "निकट-आर्कटिक राज्य, महाद्वीपीय राज्यों में से एक के रूप में पेश किया है जो आर्कटिक सर्कल के सबसे समीप हैं"। चीन ने "महान आर्कटिक शक्तियों" की श्रेणी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है और आर्कटिक को अपने राष्ट्रीय हितों का एक क्षेत्र घोषित किया है। 2018 में, बीजिंग ने आर्कटिक नीति पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जो "आइस सिल्क रोड" के निर्माण को संदर्भित करता है⁶⁹। इस प्रकार, आर्कटिक के तेल और गैस संसाधनों के अलावा, चीन उत्तरी सागर मार्ग (एनएसआर) को यूरोप के लिए एक छोटे परिवहन गलियारे और बेल्ट एंड रोड पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में महत्व देता है। इसके अलावा, परिवहन और संसाधन क्षमता का दोहन करने की चीनी व्याख्या रूस के इसे देखने के तरीके से कुछ अलग है। विशेष रूप से, चीन विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र आर्थिक गतिविधियों से इनकार नहीं करता है और आर्कटिक अक्षांशों को समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत आने वाला मानता है। चीनी भी बर्फ और समुद्र तल की सुदृढ़ जांच करते हैं, आर्कटिक में BeiDou नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के कवरेज को बढ़ाते हैं, और अभी

तक यूरोपीय भागीदारों के साथ संयुक्त अनुसंधान, संचार और आर्थिक परियोजनाओं को नहीं छोड़ा है⁷⁰।

रूस एक आर्कटिक देश है, जबकि चीन ने खुद को "निकट-आर्कटिक राज्य, महाद्वीपीय राज्यों में से एक के रूप में पेश किया है जो आर्कटिक सर्कल के सबसे समीप हैं"। चीन ने "महान आर्कटिक शक्तियों" की श्रेणी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है और आर्कटिक को अपने राष्ट्रीय हितों का एक क्षेत्र घोषित किया है।

हालांकि, रूस एनएसआर को वाणिज्यिक परियोजना के बजाय एक रणनीतिक परियोजना के रूप में देखता है⁷¹। चूंकि यह क्षेत्र रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आर्कटिक में चीन की गहरी आर्थिक भागीदारी रूस के लिए चिंता का कारण है।

इसके अलावा, कभी-कभी यह भी बताया गया है कि व्यापार करते समय, दोनों पक्षों की कंपनियों ने कठिनाइयों को व्यक्त किया है। रूस में चीनी श्रमिकों के प्रति शत्रुता की घटनाएं सामने आई हैं, विशेषकर 2020 में चीन से परे कोविड-19 के प्रसार के बाद⁷²। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि रूस चीनी नागरिकों को काम, निजी यात्राओं, शैक्षिक और पर्यटन उद्देश्यों के लिए देश में प्रवेश करने से रोकने वाले पहले देशों में से एक⁷³। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि चीनी नागरिकों पर यह पूर्ण प्रतिबंध देश में संक्रमण फैलने से बहुत पहले लगाया गया था।



रूस में चीनी श्रमिकों के प्रति शत्रुता की घटनाएं सामने आई हैं, विशेषकर 2020 में चीन से परे कोविड-19 के प्रसार के बाद।

इन असहमतियों के बावजूद, दोनों देशों के नेताओं ने साझेदारी की सकारात्मक छवि पेश करना जारी रखा है। एक नई विश्व व्यवस्था के उद्भव को सुनिश्चित करने की आम इच्छा ने दोनों के बीच इस गतिशीलता को बनाने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। आपसी समझ का यह प्रदर्शन कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में सैन्य संघर्ष के कारण आए वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवधानों के बीच स्पष्ट हुआ है। इस संदर्भ में, फरवरी 2022 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा और मार्च 2023 में राष्ट्रपति जिनपिंग की रूस यात्रा ने दोनों देशों के बीच "कोई सीमा नहीं" साझेदारी की धारणा को सुदृढ़ किया है।

6. चीन के प्रति रूस की विकसित नीति का आकलन

रूस ने 2000 से एक बहु-वेक्टर विदेश नीति का पीछा किया था, जहां "सामान्य यूरोपीय घर" बनाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने को उचित महत्व दिया गया था। रूस ने 2000 से एक बहु-वेक्टर विदेश नीति का पीछा किया था, जहां "सामान्य यूरोपीय घर" बनाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने को उचित

महत्व दिया गया था⁷⁴। यह प्रवृत्ति 2000 के दशक के मध्य तक बदलनी शुरू हुई क्योंकि पश्चिम के साथ मास्को का मोहभंग बढ़ गया। इस अवधि में यूरोपीय संघ और नाटो के विस्तार के साथ-साथ कई देशों में रंग क्रांतियों की घटनाएं देखी गईं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। इस चरण में रूसी नीति निर्माताओं को प्रभावित करने वाली एक और महत्वपूर्ण घटना 2008 में रूस-जॉर्जिया युद्ध थी। जबकि रूसी विदेश नीति में पश्चिम समर्थक दृष्टिकोण से बहाव इस समय के दौरान स्पष्ट होना शुरू हो गया था, 2014 में यूक्रेन संकट और पश्चिमी सहयोगियों द्वारा उस पर लगाए गए आगामी आर्थिक प्रतिबंधों के बाद पश्चिम से इसके अलगाव का एक नया चरण शुरू हुआ।

भले ही 2014 यूक्रेन संकट से पहले रूस-चीन साझेदारी में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उस वर्ष यूक्रेन में विकास के बाद सैन्य-तकनीकी संबंधों का दायरा व्यापक हो गया। हालांकि, इस स्तंभ ने 2018 के बाद से ठहराव के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है जब चीन को रूसी हथियारों का निर्यात चरम पर था।

मोटे तौर पर, एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ विकासशील संबंध अब रूस की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपने नए प्रतिमान के भीतर, विशेष रूप से चीन के साथ रूस के संबंधों ने पिछले आठ वर्षों में सहयोग के एक नए

चरण में प्रवेश किया है। इस भू-राजनीतिक परिदृश्य में, चीन के संबंध में रूसी विदेश नीति में निश्चित परिवर्तन हुए हैं। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चल रहे परिवर्तनों के महत्व को महसूस करते हुए, रूसी नेताओं ने धीरे-धीरे पूर्व की ओर "मुड़ना" शुरू कर दिया है और चीन को अपने करीबी सहयोगी और वैश्विक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला में मुख्य रणनीतिक भागीदार के रूप में मानते हैं। रूसी प्रतिष्ठान ने सदैव चीन के संबंध में विदेश नीति पाठ्यक्रम का पीछा करने के संदर्भ में पदों की एक निश्चित एकता का प्रदर्शन किया है। यूक्रेन संकट के बाद इस प्रवृत्ति को और गति मिली है⁷⁵।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही 2014 यूक्रेन संकट से पहले रूस-चीन साझेदारी में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उस वर्ष यूक्रेन में विकास के बाद सैन्य-तकनीकी संबंधों का दायरा व्यापक हो गया। हालांकि, इस स्तंभ ने 2018 के बाद से ठहराव के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है जब चीन को रूसी हथियारों का निर्यात चरम पर था।

रूस और चीन को एक साथ लाने वाले कारणों में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका के नेतृत्व वाली एकध्रुवीयता के विरुद्ध उनका सामान्य रुख है।

मार्च 2023 की रूस की अद्यतन विदेश नीति की अवधारणा "संबंधों को व्यापक रूप से घनिष्ठ करने और शक्ति और विकास

के मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक केंद्रों के साथ समन्वय को बढ़ाने को संदर्भित करती है, जो यूरेशियन महाद्वीप पर स्थित हैं और उन दृष्टिकोणों के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भविष्य की विश्व व्यवस्था और विश्व राजनीति की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए रूसी दृष्टिकोण के साथ सिद्धांत रूप में मेल खाते हैं⁷⁶। इस संदर्भ में, रूस की विकसित नीति अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के विकास पर केंद्रित है।

रूस और चीन को एक साथ लाने वाले कारणों में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका के नेतृत्व वाली एकध्रुवीयता के विरुद्ध उनका सामान्य रुख है। इस दृष्टिकोण को अक्टूबर 2014 में वाल्ट्वाइ क्लब चर्चा में राष्ट्रपति पुतिन के भाषण से समझा जा सकता है, जहां उन्होंने कहा कि "एकध्रुवीय दुनिया संपोषणीय नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में एकपक्षीय फरमान और अपने स्वयं के मॉडल को लागू करने से विपरीत परिणाम सामने आते हैं... संघर्षों को सुलझाने के बजाय, यह उनकी वृद्धि की ओर जाता है; संप्रभु और स्थिर राज्यों के बजाय, हम अराजकता के बढ़ते प्रसार को देखते हैं..."⁷⁷। रूस और चीन के बीच सहयोग उस चुनौती को भी बढ़ाता है जो चीन अमेरिका के लिए पेश करता है, विशेष रूप से नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में। रूस के साथ चीन के सहयोग ने अमेरिका के विरुद्ध अपनी सैन्य क्षमताओं में अंतर को पाटने, अपने तकनीकी नवाचार को



तेज करने और अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व को कमजोर करने के अपने प्रयासों को पूरा करने में मदद की है⁷⁸।

निष्कर्ष

रूस और चीन एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं जो पश्चिम-रूस या पश्चिम-चीन संबंधों में संकट से अछूती बनी हुई है। इसके विपरीत, पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका के साथ मतभेदों ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की सुविधा प्रदान की है। दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अक्सर पारस्परिक रणनीतिक विश्वास को सुदृढ़ करने, द्विपक्षीय सहयोग के पारस्परिक लाभों को घनिष्ठ करने और वैश्विक विकास में समन्वय और सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए अपनी तत्परता पर जोर दिया है। उनके बढ़ते सहयोग के संबंध में, यूक्रेन में 2014 का संकट एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से रूस के आर्थिक और राजनीतिक अलगाव की शुरुआत के बाद उनके संबंधों ने सहयोग के एक नए चरण में प्रवेश किया। यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा 2014 में रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद, देश ने उन परियोजनाओं पर सहयोग करके चीन के साथ सहयोग तेज कर दिया, जिन्हें आगे बढ़ाने से देश पहले सावधान था। आठ वर्ष बाद पश्चिम के साथ रूस के संबंध विरोध के एक नए चरण में पहुंच गए, क्योंकि रूस ने डोनेट्स्क और लुगांस्क को स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में मान्यता दी और 24 फरवरी, 2022 से यूक्रेन में अपने "विशेष सैन्य अभियान" को देखा।

यह भी स्पष्ट है कि यह साझेदारी भू-राजनीतिक आवश्यकताओं के बीच पनपी है क्योंकि दोनों अपनी महान शक्ति की स्थिति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये पहल अमेरिका के विरुद्ध प्रणालीगत संतुलन के एक पैटर्न को दर्शाती है, हालांकि औपचारिक सैन्य गठबंधन से एक कम है।

रूस-चीन संबंधों में किसी भी विकास का भारत पर प्रभाव पड़ता है। भारत रूस के साथ एक गहरी और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी साझा करता है, जिसने कई दशकों में अनुकरणीय लचीलापन दिखाया है। यूक्रेन संकट के कारण बाधाओं के बावजूद, रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। महत्वपूर्ण रूप से, यह अभी भी भारत को सैन्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने वाला एकमात्र देश बना हुआ है, एक कारक जो संबंधों में और योग्यता जोड़ता है। साथ ही, भारत भौगोलिक रूप से चीन के समीप है और उसके साथ तनावपूर्ण सीमा स्थिति साझा करता है।

हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि यह साझेदारी भू-राजनीतिक आवश्यकताओं के बीच पनपी है। ये पहल अमेरिका के विरुद्ध प्रणालीगत संतुलन के एक पैटर्न को दर्शाती है, हालांकि एक औपचारिक सैन्य गठबंधन से एक कम। यह सुविधा की साझेदारी



हैं और इस संबंध को "लेन-देन" के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो पारस्परिक लाभ उठाता है क्योंकि दोनों देश नए अंतरराष्ट्रीय "गैर-पश्चिमी" संरचनाओं का निर्माण करके अमेरिका के लिए असंतुलन बनाने के सामान्य हित को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग (SWIFT) से रूस के अलगाव ने रूस-चीन को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डी-डॉलरीकृत करने के लिए संयुक्त प्रयासों की सुविधा प्रदान की है। इसने विशेष रूप से चीन को लाभान्वित किया है क्योंकि यह वैश्विक लेनदेन में अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है।

रूस-चीन संबंधों में किसी भी विकास का भारत पर प्रभाव पड़ता है। भारत रूस के साथ एक गहरी और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी साझा करता है, जिसने कई दशकों में अनुकरणीय लचीलापन दिखाया है। यूक्रेन संकट के कारण बाधाओं के बावजूद, रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। महत्वपूर्ण रूप से, यह अभी भी भारत को सैन्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने वाला एकमात्र देश बना हुआ है, एक कारक जो संबंधों में और योग्यता जोड़ता है। साथ ही, भारत भौगोलिक रूप से चीन के समीप है और उसके साथ तनावपूर्ण सीमा स्थिति साझा करता है। इस संदर्भ में, रूस-चीन संबंधों में सकारात्मक रुझान और उनके संरेखण विश्वदृष्टि भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं क्योंकि यह पश्चिम के साथ-साथ रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करती है।

अपनी ओर से, भारत ने बाहरी कारकों के प्रभाव से प्रतिरक्षा एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी है। अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए, भारत ने रूस के साथ-साथ पश्चिमी भागीदारों के साथ अपनी भागीदारी जारी रखी है और बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की अपनी खोज के लिए एक स्वतंत्र दृष्टिकोण पेश किया है।



लेखक के बारे में



डॉ. हिमानी पंत भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से पी.एच.डी की है। उनकी डॉक्टरेट थीसिस "यूरोपीय संघ और रूस अपने सामान्य पड़ोस में: जॉर्जिया और यूक्रेन का एक मामला अध्ययन, 2004-2016" पर केंद्रित थी। आईसीडब्ल्यूए में शामिल होने से पहले, उन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में काम किया। वह 2018 में बेल्जियम के कथोलीके यूनिवर्सिटीइट ल्यूवेन में विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर भी थीं। उनका शोध रूस, यूरोपीय संघ, पूर्वी यूरोप में घटनाक्रम पर केंद्रित है।



पाद-टिप्पणियाँ

- 1 एक नए युग में प्रवेश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक सतत विकास पर रूसी संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संयुक्त बयान, क्रेमलिन, 4 फरवरी, 2022, <http://en.kremlin.ru/supplement/5770>, 5 फरवरी, 2022 को अभिगम्य।
- 2 आर्टयोम लुकिन, "रूस-चीन एंटेंट और उसका भविष्य," *अंतर्राष्ट्रीय राजनीति*, खंड 58, 2021, पृष्ठ 363-380, <https://rdcu.be/cV4L5>, 20 अगस्त, 2022 को अभिगम्य।
- 3 पूर्वोक्त
- 4 शी जिनपिंग रूस, *एमएफए चीन* की राजकीय यात्रा के लिए मास्को पहुंचे, 20 मार्च, 2023 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202303/t20230320_11045307.html, 25 मार्च, 2023 को अभिगम्य।
- 5 ज्योत्सना बखशी, रूस-चीन संबंध: भारत के लिए प्रासंगिकता, आईडीएसए और शिप्रा, 2002, पृष्ठ 2.
- 6 चार्ल्स ए. सोरल्स, "अमेरिका में खुश्चेव," *द नेशनल इंटररेस्ट*, संख्या 6, 1986, पृष्ठ 53-65. <http://www.jstor.org/stable/42894502>.
- 7 ज्योत्सना बखशी, रूस-चीन संबंध: भारत के लिए प्रासंगिकता, आईडीएसए और शिप्रा, 2002, पृष्ठ 3.
- 8 "चीन में सोवियत विशेषज्ञों के संबंध में जर्मनी की सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी की केंद्रीय समिति को खुश्चेव का पत्र," 18 जुलाई, 1960, इतिहास और सार्वजनिक नीति कार्यक्रम डिजिटल आर्काइव, एसएपीएमओ डीवाई 30/3605/25-27। ऑस्टिन जेर्सिल्ड द्वारा सीडब्ल्यूआईएचपी के लिए प्राप्त और अनुवादित, <http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116831>.
- 9 थॉमस डब्ल्यू. रॉबिन्सन, चीन-सोवियत सीमा विवाद-रैंड कॉर्पोरेशन, 1970, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2019/RM6171.pdf.
- 10 डोनाल्ड एस. ज़ागोरिया, मॉस्को-बीजिंग डेटेंटे, विदेश मामले, 1983, <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1983-03-01/moscow-beijing-détente>.
- 11 पूर्वोक्त
- 12 XXviii सीपीएसयू कांग्रेस, दस्तावेज और संकल्प, 1986, *संबद्ध*, नई दिल्ली, पृष्ठ 93-94।

- 13 गोर्बाचेव के भाषण के कुछ अंश, *न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए विशेष*, 29 जुलाई, 1986, <https://www.nytimes.com/1986/07/29/world/excerpts-from-gorbachev-s-speech.html>.
- 14 रूस ने चीन से अमूर और उससुरी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया-ऐगुन (1858) और पेकिंग (1860) की संधियों के माध्यम से-चीनी, कोरियाई और जापानी नागरिकों की काफी आबादी ने रूसी सुदूर पूर्व में रहना और काम करना जारी रखा।
- 15 डोनाल्ड एस. जागोरिया, मॉस्को-बीजिंग डेटेंटे, विदेश मामले, 1983, <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1983-03-01/moscow-beijing-detente>.
- 16 शर्मन गार्नेट, "चीन-रूसी रणनीतिक साझेदारी की चुनौतियां," *वाशिंगटन क्वार्टरली*, खंड 24, संख्या 4, 2001, पृष्ठ 41-54, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1162/016366001317149174?casa_token=lpEvUtQWKz0AAAAA:GfPqHSw38U_-8kxEQGsV-ekf7kYjQSBp1Mt6vXVrPcUTI
T6ooooYdngvgbk37WMFZR6Ebh1J8 W1, 2 जून, 2022 को अभिगम्य।
- 17 एलेक ब्लिवास, चीन-रूसी सैन्य-तकनीकी सहयोग: ए प्राइमर, मार्च 2020, सीएसआईएस, http://defense360.csis.org/wp-content/uploads/2020/03/Blivas_Russia-China-MTC_Brief.pdf
- 18 डेंग ज़ियाओपिंग के चयनित कार्य, खंड 3 (पीपुल्स पब्लिशर: बीजिंग), 1993, <https://dengxiaopingworks.wordpress.com/selected-works-vol-3-1982-1992/>
- 19 Vladimir Putin Met with Jiang Zemin, President of the People's Republic of China, *The Kremlin*, July 18, 2000, व्लादिमीर पुतिन ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति जियांग जेमिन से भेंट की, *क्रेमलिन*. 18 जुलाई, 2000. <http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/38413>.
- 20 पुतिन ने रणनीतिक धुरी को सुदृढ़ करने की आशा में चीन का दौरा किया, *द न्यूयॉर्क टाइम्स*, 18 जुलाई, 2000, <https://www.nytimes.com/2000/07/18/world/putin-visits-china-in-hope-of-strengthening-a-strategic-axis.html>.
- 21 एससीओ एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना की घोषणा 15 जून, 2001 को शंघाई में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान द्वारा की गई थी। यह शंघाई फाइव के तंत्र से



- पहले था। जून 2002 में, सेंट पीटर्सबर्ग में राज्य के प्रमुखों की परिषद की बैठक में एससीओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे, और 19 सितंबर, 2003 को लागू हुआ। यह एक बुनियादी वैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों और सिद्धांतों, इसकी संरचना और मुख्य गतिविधियों को तय करता है। 8-9 जून, 2017 को अस्ताना ने एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की एक ऐतिहासिक बैठक की मेजबानी की, जिसके दौरान संगठन के सदस्य राज्य का दर्जा भारत गणराज्य और इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान को दिया गया। अधिक जानकारी के लिए देखें एससीओ सचिवालय, http://eng.sectesco.org/about_sco/, पर उपलब्ध है 10 अक्टूबर, 2022 को अभिगम्य।
- 22 "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रूसी संघ के बीच अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि," *एमएफए चीन*, 24 जुलाई, 2001, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/200107/t20010724_679026.html, 10 जुलाई, 2022 को अभिगम्य।
- 23 पूर्वोक्त
- 24 "चीन ने रूस के साथ सीमा सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए, *रॉयटर्स*, 21 जुलाई, 2008, <https://www.reuters.com/article/us-china-russia-border-idUKPEK29238620080721>, 8 अगस्त, 2022 को अभिगम्य।
- 25 पूर्वोक्त
- 26 एसआईपीआरआई, "रूस के साथ चीन के ऊर्जा और सुरक्षा संबंध," 1 सितंबर, 2011, 20 जून, 2022 को अभिगम्य।
- 27 सुखोई समुद्री डकैती: रूस ने चीन पर मुकदमा करने की धमकी दी, *टाइम्स ऑफ इंडिया*, 23 अप्रैल, 2008, **Error! Hyperlink reference not valid.** indiatimes.com/articleshow/2973405.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.
- 28 माइकल एस चेस एट अल, "रूस-चीन संबंध सामान्य जमीन और रणनीतिक दोष रेखा का आकलन करते हैं," जुलाई 2017, https://carnegieendowment.org/files/SR66_Russia-ChinaRelations_July2017.pdf.
- 29 सिंककोनेन, "चीन-रूस सुरक्षा सहयोग। सीमाओं के साथ भू-राजनीतिक संकेत, "एफआईआईए ब्रीफिंग पेपर 231, 2018, <https://Error! Hyperlink reference>

not valid.

- 30 पूर्वी भागीदारी (ईएपी) यूरोपीय पड़ोस नीति का एक विशिष्ट पूर्वी आयाम है जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ और इसके छह पूर्वी यूरोपीय और दक्षिण काकेशस 'भागीदार देशों' के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ और गहरा करना है: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्दोवा गणराज्य और यूक्रेन। अधिक जानकारी के लिए <https://euneighbourseast.eu/policy/> देखें
- 31 2013 में, तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एक एसोसिएशन समझौते से अचानक इनकार कर दिया, जिससे यूक्रेन के मैदान में विरोध प्रदर्शनों की एक लहर शुरू हो गई, जो आगामी महीनों में हिंसक हो गई। यूरोपीय संघ के समझौते को छोड़ने का यानुकोविच का निर्णय रूस को नाराज नहीं करने के तर्क पर आधारित था। उक्त समझौते से अचानक प्रस्थान और छोड़ने के बढ़ते दबाव पर व्यापक विरोध के साथ, यानुकोविच 22 फरवरी, 2014 को कीव से भाग गया और रूस में शरण ली। इसके तुरंत बाद, रूस ने क्रीमियन प्रायद्वीप में एक (बहस) जनमत संग्रह आयोजित किया और उस पर कब्जा कर लिया। जबकि क्रीमिया की अंतरराष्ट्रीय स्थिति अभी भी विवादित बनी हुई है और इसे "एनेक्सेशन" माना जाता है, रूस क्रीमिया को अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है। अधिक जानकारी के लिए यूक्रेन संकट और उसके बारे में देखें http://www.pant.org/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=7147&lid=4835, 10 मार्च, 2023 को अभिगम्य।
- 32 " ब्रह्मा चेलानी, "क्या रूस को दंडित करना अपने आप में एक अंत बन सकता है?", "द हिल, <https://thehill.com/opinion/international/3257740-can-punishing-russia-become-an-end-in-itself/>, 10 सितंबर, 2022 को अभिगम्य।
- 33 दिमित्री ट्रेनिन, "रूस और 'गैंड यूरेशिया': क्या यह काम करेगा?," *क्षितिज: अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सतत विकास जर्नल*, खंड 9, 2017, पृष्ठ 106119, <https://www.jstor.org/stable/48573711>.
- 34 भारत गणराज्य में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास, "रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन ने वांग यी के साथ भेंट की," 8 अप्रैल, 2015, <http://in.china-embassy.org/eng/zgxw/t1253304.htm>.
- 35 राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में रूस की विजय की 70^{वीं} वर्षगांठ के



- उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया, एफएमपीआरसी, 9 मई, 2015, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/2015zt/xjpcxelsjngwzssl70znqdbfshskstbels/201505/t20150512_704934.html.
- 36 रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने 1999 में सीमा शुल्क संघ और सामान्य आर्थिक स्थान बनाने पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि 1994 में कजाख राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव द्वारा प्रस्तावित मॉडल पर आधारित थी, जिन्होंने "माल, सेवाओं, पूंजी और कार्यबल के मुक्त आंदोलन" की सुविधा के लिए एक एकीकृत सीमा शुल्क क्षेत्र के गठन की कल्पना की थी। इससे एक वर्ष बाद यूरोशियन आर्थिक समुदाय का निर्माण हुआ। मई 2014 में, यूरोशियन आर्थिक संघ की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। अपने वर्तमान रूप में, ईएईयू पांच सदस्य राज्यों का एक आर्थिक संघ है: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस। यह इन भाग लेने वाले देशों के बीच माल, सेवाओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी सीमाओं के बावजूद, विशेष रूप से आर्थिक, ईएईयू को रूस के लिए सोवियत अंतरिक्ष में अपना प्रभाव बनाए रखने के साधन के रूप में देखा जाता है।
- 37 यूरोशियन आर्थिक संघ और सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट के निर्माण के संयुग्मन में सहयोग पर रूसी संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संयुक्त वक्तव्य, *क्रेमलिन*, 8 मई, 2015, <http://kremlin.ru/supplement/4971>, 20 जून, 2022 को अभिगम्य।
- 38 "बीआरआई ने चीन-रूस संबंधों को सुदृढ़ किया है," *चाइना डेली*, 2019 में उद्धृत किया गया है। <https://www.chinadaily.com.cn/a/201904/22/WS5cbd237aa3104842260b7792.html>, 22 अप्रैल, 2023 को अभिगम्य।
- 39 एक नए युग में प्रवेश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक सतत विकास पर रूसी संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संयुक्त वक्तव्य, *क्रेमलिन*, 4 फरवरी, 2022, <http://en.kremlin.ru/supplement/5770>, 15 सितंबर, 2023 को अभिगम्य।
- 40 "रूसी संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर समझौता," *एमएफए रूस*, https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/

- nato/1790803/?lang=en&clear_cache=Y, 20 फरवरी, 2022 को अभिगम्य।
- 41 "अमेरिकी इंटेल ने रूस की आक्रमण योजनाओं की सटीक भविष्यवाणी की। क्या इससे कोई फर्क पड़ा?," *सीएनबीसी*, 26 फरवरी, 2022, <https://www.cnbc.com/2022/02/25/us-intel-predicted-russias-invasion-plans-did-it-matter.html>.
- 42 निरुपमा सुब्रमण्यन ने कहा, "चीन-रूस संबंध," *द इंडियन एक्सप्रेस*, <https://indianexpress.com/article/explained/explained-the-china-russia-relationship-ukraine-putin-xi-jingping-7763398/>, 10 फरवरी, 2022 को अभिगम्य।
- 43 पूर्वोक्त
- 44 यूक्रेन के आसपास तनाव दिसंबर 2021 में शुरू हुआ जब रूस ने अमेरिका और नाटो से सुरक्षा गारंटी मांगी ताकि आगे किसी भी विस्तार से बचा जा सके। जनवरी की शुरुआत में नाटो-रूस परिषद की बैठक में हुई बातचीत बैठक के बाद आम सहमति पर पहुंचने में विफल रही।
- 45 नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि नाटो की ओपन डोर पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इस मामले पर बातचीत और आगे की बातचीत फिर से शुरू करने की आवश्यकता व्यक्त की। बाद में उसी महीने, अमेरिका और नाटो ने रूस के प्रस्ताव का जवाब दिया। हालांकि प्रतिक्रिया की सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया गया था, यह स्पष्ट था कि रूसी प्रस्तावों पर सहमति नहीं हुई थी। अधिक जानकारी के लिए देखें यूक्रेन में वर्तमान स्थिति और रूसी विदेश नीति पर इसका प्रभाव, https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=7725&lid=5149.
- 46 रूसी संघ, क्रेमलिन के राष्ट्रपति द्वारा संबोधन, 24 फरवरी 2022, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843>
- 47 पी.एस. राघवन, "यूक्रेन संकट: उभरती हुई विश्व व्यवस्था के लिए बदलाव का एक बिंदु," *भारतीय वैश्विक परिषद*, 2022, https://www.icwa.in/showfile.php?lang=1&level=3&ls_id=8690&lid=5690.
- 48 यूक्रेन संकट के राजनीतिक निपटान पर चीन की स्थिति, *एमएफए चीन*, 24 फरवरी, 2023, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202303/t20230320_11045307.



html.

- 50 रूसी-चीनी वार्ता, *क्रेमलिन*, 21 मार्च, 2023, <http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/70748>.
- 51 पूर्वोक्त
- 52 वेंकटेश वर्मा, अतिशयोक्ति के जोखिम: शी यात्रा के बाद चीन के साथ रूस के संबंधों का क्या मतलब है, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, 6 अप्रैल 2023, [https://Error!Hyperlink reference not valid. april/06/risks-of-exaggeration-what-to-make-of-russias-relations-with-china-after-the-xi-visit](https://Error!Hyperlink%20reference%20not%20valid.april/06/risks-of-exaggeration-what-to-make-of-russias-relations-with-china-after-the-xi-visit), 20 अप्रैल, 2023 को अभिगम्य।
- 53 एस किसेलियोव, "एनर्जेटिकहेस्कियेमोस्टी एवराजी। नेजाविसिमाया," गजेटा, 24.2019. अक्टूबर http://www.ng.ru/economics/2019-10-24/100_193324102019.html.
- 54 "रूस, चीन यूरो में निपटान के लिए नई पाइपलाइन के माध्यम से 30 वर्ष के गैस सौदे पर सहमत हुए," *रॉयटर्स*, 4 फरवरी, 2021, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-russia-china-agree-30-year-gas-deal-using-new-pipeline-source-2022-02-04/>, 11 मार्च, 2022 को अभिगम्य।
- 55 रूसी-चीनी वार्ता, *क्रेमलिन*, 31 मार्च, 2023, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/70748>. 1 अप्रैल, 2023 को अभिगम्य।
- 56 चीन-रूस प्री-2030 योजना का उद्देश्य व्यापार की गुणवत्ता में सुधार करना है, *ग्लोबल टाइम्स*, 22 मार्च 2023, <https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287763.shtml>.
- 57 बैंक ऑफ रूस, बाहरी क्षेत्र के सांख्यिकी, https://www.cbr.ru/eng/statistics/macro_itm/svs/
- 58 सीआरएस रिपोर्ट, रूस के साथ चीन के आर्थिक और व्यापारिक संबंध, 24 मई, 2022, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12120>.
- 59 यूएसटीआर, माल और सेवाओं में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दिसंबर और वार्षिक 2022, <https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china>.
- 60 पश्चिमी देशों ने बीजिंग में विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन के बाद 1989 में चीन

- पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया था। अधिक जानकारी के https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/china लिए देखें, 20 अक्टूबर, 2022 को अभिगम्य।
- 61 "चीन और रूस ने भूमध्य सागर में नौसैनिक ड्रिल का समापन किया," *द डिप्लोमेट*, 22 मई, 2015, [https:// thedi diplomat.com/2015/05/china-and-russia-conclude-naval-drill-in-mediterranean/](https://thedi diplomat.com/2015/05/china-and-russia-conclude-naval-drill-in-mediterranean/), 20 सितंबर, 2022 को अभिगम्य।
- 62 चीन में रूसी सैन्य हस्तांतरण की बदलती प्रकृति और निहितार्थ," 21 जून, 2021, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, <https://www.csis.org/analysis/changing-nature-and-implications-russian-military-transfers-china>, 14 अगस्त, 2022 को अभिगम्य।
- 63 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-22 में, रूस ने 47 राज्यों को प्रमुख हथियार वितरित किए और कुल वैश्विक हथियार निर्यात का 16 प्रतिशत हिस्सा था। रूसी हथियारों का निर्यात 2008-12 और 2013-17 के बीच स्थिर रहा, लेकिन 2013-17 और 2018-22 के बीच 31 प्रतिशत की गिरावट आई। 2018 और 2019 में हथियारों के निर्यात की वार्षिक मात्रा पिछले 20 वर्षों में से प्रत्येक के समान स्तर पर या उससे अधिक थी, लेकिन 2020, 2021 और 2022 में काफी कम स्तर पर थी
- 64 इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर में रुझान, 2022, *एसआईपीआरआई फैक्ट शीट*, https://www.sipri.org/sites/default/files/202303/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf.
- 65 ए. शाह, "रूस ने अपनी बेल्ट ढीली की," *विदेश नीति*, 2020, <https://foreignpolicy.com/2020/07/16/russia-china-belt-and-road-initiative/>, 12 नवंबर, 2022 को अभिगम्य।
- 66 ओल्गा अलेक्सीवा और फ्रेडेरिक लासेरे, चीन-रूसी संबंधों का विकास जैसा कि मास्को से देखा गया है: रणनीतिक तालमेल की सीमाएं, <https://journals.openedition.org/chinaperspectives/8197#tocto2n3>.
- 67 दिमित्री ट्रेनिन, "रूस और 'ग्रेंड यूरोशिया': क्या यह काम करेगा?," *क्षितिज: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सतत विकास के जर्नल*, 2017, खंड 9, पृष्ठ 106-119, <https://www.jstor.org/stable/48573711>.
- 68 पुतिन: सुदूर पूर्व का विकास रूस के लिए 21^{वीं} सदी की राष्ट्रीय प्राथमिकता है, 9 नवंबर,



- 2017, <https://forumvostok.ru/en/news/v-putin-dlya-rossii-razvitie-dalnego-vostoka-yavlyaetsya-natsionalnym-prioritetom-xxi-veka/>.
- 69 सर्गेई इवानोव एट अल, "कोविड-19 के युग में चीन पर रूसी जनता की राय: एक संदिग्ध सहयोगी," *सेंट्रल यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया स्टडीज*, <https://ceias.eu/wp-content/uploads/2021/08/RUS-poll-report.pdf>.
- 70 पूर्ण पाठ: चीन की आर्कटिक नीति, राज्य परिषद- पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 26 जनवरी 2028, https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
- 71 एंड्री गुबिन, आर्कटिक में रूस के रुख के सैन्य पहलू, रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद, 23 सितंबर, 2022, <https://russiancouncil.ru/en/analytcs-and-comments/analytcs/military-aspects-of-russia-s-stance-in-the-arctic/>.
- 72 व्लादिमीर पेत्रोव्स्की, विशेषज्ञों ने आर्कटिक में एशियाई देशों के साथ रूस के सहयोग पर चर्चा की, 29 नवंबर, 2022, रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद, https://russiancouncil.ru/en/news/experts-discuss-russia-s-cooperation-with-asian-countries-in-the-arctic/?sphrase_id=97401509.
- 73 लिंडसे मैज़लैंड, चीन और रूस: दो सत्तावादी शक्तियों के बीच संबंधों की खोज, सीएफआर, 14 जून, 2022, <https://www.cfr.org/backgrounder/china-russia-relationship-xi-putin-taiwan-ukraine>.
- 74 "रूस कोरोनावायरस के जवाब में चीनी नागरिकों को निर्वासित करने वाला पहला देश बन सकता है। <https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-02-28/russian-entry-ban-on-chinese-nationals-has-some-seeing-red>, 31 मार्च, 2022 को अभिगम्य।
- 75 "जर्मनी के संघीय गणराज्य के बंडेस्टैग में भाषण," *क्रेमलिन*, 25 सितंबर, 2001, <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/21340>, 16 जुलाई, 2022 को अभिगम्य।
- 76 अनास्तासिया सोलोमैंत्सेवा, "रूस की नजर में चीन का 'उदय': खतरों या नए अवसरों का स्रोत?," *कनेक्शन* 14, संख्या 1, 2014, पृष्ठ 3-40, <http://www.jstor.org/stable/26326384>.
- 77 रूसी संघ की विदेश नीति की अवधारणा, *एमएफए रूस*, 31 मार्च, 2023, https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/

- 78 "वाल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब, मॉस्को की बैठक," 24 अक्टूबर, 2014, <http://eng.kremlin.ru/news/23137>, 20 जुलाई, 2022 को अभिगम्य।
- 79 एंड्रिया केंडल-टेलर और डेविड शुलमैन, "गहरा रूस-चीन साझेदारी को नेविगेट करना," *सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी*, 14 जनवरी, 2021, 22 जनवरी 2023 को अभिगम्य।
- 80 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-22 में, रूस ने 47 राज्यों को प्रमुख हथियार वितरित किए और कुल वैश्विक हथियार निर्यात का 16 प्रतिशत हिस्सा था। रूसी हथियारों का निर्यात 2008-12 और 2013-17 के बीच स्थिर रहा, लेकिन 2013-17 और 2018-22 के बीच 31 प्रतिशत की गिरावट आई। 2018 और 2019 में हथियारों के निर्यात की वार्षिक मात्रा पिछले 20 वर्षों में से प्रत्येक में समान स्तर पर या उससे अधिक थी, लेकिन 2020, 2021 और 2022 में रूस से चीन को हथियार निर्यात, 1992-2022 एसआईपीआरआई आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस में काफी कम स्तर पर थी।
- <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>







भारतीय वैश्विक
परिषद

संप्र हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001, भारत
टेलीफोन: +91-11-2331 7242 | फैक्स: +91-11-2332 2710

www.icwa.in